



CB  
2/8/85

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 636]  
No. 636]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 1984/पौष 8, 1906  
NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 1984/PAUSA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1984

का. आ. 973 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84:—  
केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और  
नागरिक पुनर्निर्माण (औद्योगिक विकास विभाग) के  
आदेश सं. का.आ. 319 (अ) 18कक/उ.वि.वि.अ./76  
तारीख 27 अप्रैल, 1976, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात्  
उक्त आदेश कहा गया है) में संशोधन प्लानेट्रीज लिमिटेड,  
गाम्पांग, जम्मू कश्मीर नामक संशुद्ध औद्योगिक उपक्रम  
का प्रवन्ध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख  
भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने  
के लिए जम्मू कश्मीर प्लानेट्रीज लिमिटेड को प्रधिकृत किया  
था,

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि  
लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच  
वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभाव में बना रहे  
31 दिसम्बर 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मि-  
लित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिये सम-  
न्वय पर निर्देश जारी किये थे [द्वितीय भारत सरकार के

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं.  
का.आ. 318(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./81, तारीख 25  
अप्रैल, 1981, सं. का.आ. 287(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./  
82, 26 अप्रैल 1982, सं. का.आ. 763(अ)/18कक/उ.वि.-  
वि.अ./82, तारीख 25 अक्टूबर, 1982, सं. का.आ.  
233 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83, तारीख 28 मार्च,  
1983, सं. का.आ. 695 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./83,  
तारीख 29 दिसम्बर, 1983 सं. का.आ. 227 (अ)/18कक/  
उ.वि.वि.अ./84, तारीख 30 मार्च 1984, का.आ. 473  
(अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84 तारीख 28 जून, 1984  
आर का आ. 748 (अ)/18कक/उ.वि.वि.अ./84 तारीख  
28 दिसम्बर 1984]

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित  
में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1985 तक  
की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के  
के लिए प्रभाव में बना रहे,

अ. अब केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन)  
अधिनियम, 1951 (1951 का 65) को धारा 18क  
का उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पाठन धारा  
18क का उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावोत्पन्न रहेगा।

[क. सं. 2(6)/81 सी.यू.एस.]

ए. पी. सरवान, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 29th December, 1984

S.O. 973(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319(E)|18AA|IDRA|76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the Industrial undertaking known as Messrs Ply-board Industries Limited, Panipore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981.

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid,

had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1984 [vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 318(E)|18AA|IDRA|81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)|18AA|IDRA|82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th October, 1982, S.O. 233(E)|18AA|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, S.O. 695(E)|18AA|IDRA|83, dated the 29th September, 1983, S.O. 227(E)|18AA|IDRA|84, dated the 30th March, 1984, S.O. 473(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984 and S.O. 748(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th September, 1984];

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985.

[File No. 2(6)|81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.